प्रेस–नोट

दिनांकः 10 अक्टूबर, 2024

आयोग का यूपीएसएलडीसी द्वारा योजित प्रथम टैरिफ याचिका पर एलडीसी टैरिफ का निर्धारण

यूपीएसएलडीसी द्वारा प्रदत्त सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एलडीसी शुल्क रुपये 536.81/ मेगावाट/माह तय किया गया

पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड के संचालन और प्रभावी उपयोग के लिए निर्देश

आयोग समय समय पर यूपीपीटीसीएल को निर्देश देता रहा है कि यूपीएसएलडीसी को यूपीटीसीएल से पृथक एक स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापित किया जाए, जिससे यूपीएसएलडीसी की रिंग फेंसिंग और कार्यत्मक स्वायत्तता सुनिश्चित हो सके। अन्ततः यूपीएसएलडीसी को कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत 22 अगस्त, 2022 को एक लि0 कम्पनी के रूप में पंजीकृत किया गया। यूपीईआरसी (स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर की फीस और अन्य सम्बन्धित मामलों) विनियमावली, 2020 के अनुसार एलडीसी टैरिफ निर्धारण के लिए यूपीएसएलडीसी द्वारा याचिका दायर की गयी।

आयोग ने 10 जून, 2024 के आदेश के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 के ट्रूअप, वित्तीय वर्ष 2023–24 की वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा (एपीआर) और वित्तीय वर्ष 2024–25 की सकल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) निर्धारण के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट लोड डिस्पैच सेंन्टर अर्थात यूपीएसएलडीसी द्वारा प्रस्तुत याचिका को स्वीकार कर लिया।

याचिका की स्वीकृति के उपरान्त सभी हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की गयीं, जिसके लिए यूपीएसएलडीसी द्वारा समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करायी गयी। आयोग ने हितधारकों और बड़े पैमाने पर जनता के सुझावों /आपत्तियों पर विचार करने के लिए दिनांक 10 जुलाई, 2024 को सार्वजनिक जनसुनवाई आयोजित की, जिससे सभी को एआरआर और एसएलडीसी के टैरिफ को अन्तिम रूप देने और निर्धारण करने से सम्बन्धित प्रकरणों पर विचार व्यक्त करने का पर्याप्त अवसर मिला।

आयोग ने विभिन्न हितधारकों द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियों पर विचार करने के उपरान्त दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 को टैरिफ आदेश जारी किया। इसके मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं:–

i) आयोग ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए मासिक एलडीसी चार्जेज रू0 536.81/एमडब्ल्यु/माह अनुमोदित किया है। आयोग ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए एलडीसी टैरिफ निर्धारण हेतु 55,649.60 मैगावाट की अनुबन्धित (कमीशन्ड) क्षमता पर विचार किया है। आयोग द्वारा अनुमोदित एलडीसी टैरिफ का विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया है:–

वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु अनुमोदित एलडीसी चार्जेज

विवरण	यूनिट	वित्तीय वर्ष 2024-25	
		याचिकाकर्ता द्वारा क्लेम्ड	आयोग द्वारा अनुमोदित
Annual Revenue Requirement (ARR) for FY 2024-25	Rs. Lakh	4,674.37	3,778.71
Revenue from Operations for FY 2024-25	Rs. Lakh	2,337.52	1,745.52
Revenue Gap/(Surplus) of ARR for FY 2024-25	Rs. Lakh	2,336.85	2,033.19
Revenue Gap of FY 2022-23 (considering carry forward cost)	Rs. Lakh	-	1,551.60
Net Revenue Gap to be recovered from LDC Charges (considering carry forward True-Up Gap of FY 2022-23)	Rs. Lakh	2,336.85*	3,584.79
Contracted/ tied up commissioned capacity	MW	55,649.60	55,649.60
Monthly LDC Charges	Rs./MW/Month	349.93	536.81

*याचिकाकर्ता ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के ट्रूअप अन्तर पर विचार किये बिना वित्तीय वर्ष 2024–25 के सकल एआरआर की गणना की है।

ii) आयोग ने यूपीएसएलडीसी को राज्य विद्युत समिति (एसपीसी) की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि यूपीएसएलडीसी की वेबसाइट के होमपेज पर यूपी–एसपीसी का एक पृथक लिंक बनाया जाय जहॉ प्रासंगिक डेटा/दस्तावेज अपलोड किया जाय।

iii) राज्य में पावर सिस्टम डेवलपमेंट फण्ड (पीएसडीएफ) की नोडल एजेंसी होने के नाते एसएलडीसी को निर्देशित किया गया कि वह पीएसडीएफ के अन्तर्गत प्रस्तावों को तुरंत और समय पर प्रबन्धित करे और यूपीईआरसी (पावर सिस्टम डेवलपमेंट फण्ड) विनियमावली, 2023 के अनुसार अनुमोदन के लिए आयोग के समक्ष प्रस्तुत करे।

iv) इसके अतिरिक्त, आयोग ने पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (SCADA)/ ऊर्जा प्रबन्धन प्रणाली (ईएमएस) प्रणाली, साइबर सुरक्षा संचालन, कर्मचारियों के प्रशिक्षण आदि विषयों के कियान्वयन सम्बन्धी के कार्यान्वयन कई अन्य निर्देश प्रदान किये।

टैरिफ आर्डर आयोग की वेबसाइट www.uperc.org पर अपलोड है।

(शैलेन्द्र गौर)

सचिव

PRESS NOTE

Dated: October 10, 2024

UPERC determines LDC charges on first Tariff Petition filed by UPSLDC

Fixes LDC charges at Rs. 536.81/ MW/month for availing services provided by UPSLDC.

Gives directions for operationalization and effective utilisation of Power System Development Fund.

The Commission, from time to time, had been directing UPPTCL to establish UPSLDC as an independent body separate from UPPTCL so that ring-fencing and functional autonomy of UPSLDC is ensured. Thus, UPSLDC was finally incorporated as a limited company on August 22, 2022, under the Companies Act, 2013 thus, it filed its first Petition for determination of LDC charges as per UPERC (Fees & Charges of State Load Despatch Centre and other related matters) Regulations, 2020.

The Commission, vide Order dated June 10, 2024, had admitted the Petition filed by the Uttar Pradesh State Load Despatch Centre i.e. UPSLDC for True Up of FY 2022-23, Annual Performance Review (APR) for FY 2023-24 and Determination of Aggregate Revenue Requirement (ARR) & SLDC Charges for FY 2024-25.

After admission, comments were invited from all stakeholders for which a Public Notice was issued by the UPSLDC in newspapers. Further the Commission also published a public notice in newspapers informing the date of public hearing. The Commission conducted the Public Hearing on July 10, 2024, to consider the suggestions / objections of the stakeholders and the public at large, thereby giving ample opportunity to all to express their views on the matters pertaining to finalization and determination of ARR & SLDC Charges.

The Commission after considering the submissions made by various stakeholders has finalized and issued the Tariff Order on October 10, 2024. The highlights of the same are as below:

(i) The Commission has approved the monthly LDC Charges of Rs. 536.81 / MW/ Month for FY 2024-25. The Commission has considered 55,649.60 MW of contracted / tied up commissioned capacity handled for determination of LDC Charges for FY 2024-25. The details of LDC charges approved by the Commission are shown in the Table below:

APPROVED LDC CHARGES FOR FY 2024-25

Particulars	Units	FY 2024-25	
		Claimed by Petitioner	Approved by Commission
Annual Revenue Requirement (ARR) for FY 2024-25	Rs. Lakh	4,674.37	3,778.71
Revenue from Operations for FY 2024-25	Rs. Lakh	2,337.52	1,745.52
Revenue Gap/(Surplus) of ARR for FY 2024-25	Rs. Lakh	2,336.85	2,033.19
Revenue Gap of FY 2022-23 (considering carry forward cost)	Rs. Lakh	-	1,551.60

Particulars	Units	FY 2024-25	
		Claimed by Petitioner	Approved by Commission
Net Revenue Gap to be recovered from LDC Charges (considering carry forward True-Up Gap of FY 2022-23)	Rs. Lakh	2,336.85*	3,584.79
Contracted/ tied up commissioned capacity	MW	55,649.60	55,649.60
Monthly LDC Charges	Rs./MW/Month	-	536.81

**The Petitioner has computed the Net ARR for FY 2024-25 without considering the True-Up Gap of FY 2022-23.*

(ii) The Commission has directed UPSLDC to conduct meetings of the State Power Committee (SPC) regularly and ensure that a separate link of UP-SPC is created on the homepage of UPSLDC's website where relevant data/documents are uploaded regularly.

(iii) UPSLDC, being the nodal agency for PSDF in the State, is directed to promptly and in timely manner process the proposal(s) under PSDF and submit the same before the Commission for approval in accordance with UPERC (Power System Development Fund) Regulations, 2023.

(iv) Further, the Commission has provided various other directions regarding implementation of Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) / Energy Management System (EMS) system, Cyber Security Operation Centre and Training of the staff etc.

The Tariff Order has been uploaded at **www.uperc.org** .

(Shailendra Gaur)
Secretary